[श्री बी॰ भार॰ मुक्ल]
कि गवर्नमेंट की नीतियों को, गवर्नमेंट के कामों
को, गवर्नमेंट के कानून को बदलने के लिए
धगर किसो किस्म का समालोचना की जाती
है या गवर्नमेंट का कानून के द्वारा बदलने का
प्रयत्न किया जाता है तो वह इस के भन्तर्गत
नहीं भाता है।

इन्ही शब्दो के साम मै इस विल का समर्थन करता हूं।

17.54 hrs.

Re. BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH); I have an announcement to make.

Some hon. Members this side as well as that side told me that it would be desirable to have the discussion set down to-day under Rule 193 on some other day rather than at the fag end of today I consulted the Opposition leaders. Now it is agreed that it will not be taken up to-day but it will be taken up on the 5th February if possible after the government business is over and if for any reason, the government business is not over on that day, then we will have to sit on the 6th also for this and also for such of the government business as may be left over on the 5th. If we are sitting on the 6th, 6th being a Friday, only the government business will be taken and also this discussion, and no other private member's business.

श्री मरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) ध चैयरमेन साहब, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि माननीय संसदीय मंत्री जी ने जो विचार रखा है वह ठीक विचार है। इस के लिए पूरा एक दिन का डिस्कंतन चाहिए जैसा कि

बाप चाहते हैं भीर जैसा कि सबन के इस बोर

के भीर उधर के सदस्य चाहते हैं, , तैकिन

इस बीच में चैयर मैंन साहब, मैं एक निवेदन
भाप से करना चाहता हूं, और यहां पर बाख

मंत्री श्री शाह नवाज खां भी बैठे हुए हैं, कि

यू० पी० में गन्ने के किसानों को कन्नों का

दाम नहीं मिल रहा है। इस बारे में भाज ही

प्रधान मंत्री जी के साथ, यू० पी० के पालियामेंट

के मम्बरों की और उस मे माननीय मुख्य मंत्री
भी थे, जो बातचीत हुई उसमें यही कहा गया
था कि हम चाहते हैं कि इस के बारे में पहल
करें जिस से कम से कम कैन-प्राइस का मूल्य
नो तय हो जाए।

इस सम्बन्ध में मै यह भी कहना चाहता हूं कि जहा तक इस प्रश्न का सवाल है, इस का सम्बन्ध पूरी शूगरकेन पाखिमी से है। यह केवल केन-प्राइस का मवाल नही है। हर साल शूगर केन का एरियर बाकी रह जाता है। इसलिए पूरी शूगर पालिसी का मैंटर इस में इन्वाल्ध्ड है। मै चाहता हू कि झगर किसी भी तरीके से कैन-प्राइस का मामला हल कर दिया जाता है, तो भी इस डिस्कशन को पोस्टरोन न किया जाए।

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: As for the time, it will be discussed by the Business Advisory Committee if it has not already done so. Whatever the Business Advisory Committee decides, will be adhered to.